शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

40% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों की कराई गई दक्षता परीक्षा

शिक्षकों ने किताब देखकर परीक्षा दी फिर भी सता रहा फेल होने का डर

फेल होने वाले शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए फिर दिया जाएगा अवसर

प्रदेश टुडे संवाददाता, ग्वालियर

प्रदेश के जिन हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों का रिजल्ट खराब रहा था, उनके शिक्षकों की दक्षता परीक्षा कराई जा चुकी है। शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद भी शिक्षा विभाग ने परीक्षा करा दी। इसमें जो शिक्षक शामिल हुए,उन्होंने किताब में से देखकर प्रश्न को हल किया। बावजूद इसके कई शिक्षकों को फेल होने की चिंता सता रही है। दक्षता परीक्षा का मूल्यांकन भी परीक्षा वाले दिन रविवार को ही करा दिया गया। परिणाम अभी गोपनीय रखा गया है।

सोमवार को छह हजार से अधिक शिक्षक परीक्षा देंगे। ग्वालियर,दतिया सहित अन्य कई जिलों में शिक्षकों ने परीक्षा का विरोध किया। सत्र 2019-20 में दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम 40 फीसदी से कम आया है। उन स्कूलों के शिक्षकों की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दक्षता मूल्यांकन

परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा परिणाम कम होने पर शिक्षकों को दो माह की अवधि दक्षता सुधार के लिए दी जाएगी।

बता दें कि जिला स्तर के इन शिक्षकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में दोबारा परीक्षा होगी। इसमें भी शिक्षक फेल होते हैं, तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। बता दें, कि पिछले साल भी स्कूल शिक्षा विभाग ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में 30 फीसद से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा दो बार ली थी। दोबारा फेल होने पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। हालांकि इस बार भी शिक्षक संगठनों ने परीक्षा का विरोध किया। मगर परीक्षा को टाला नहीं किया। शिक्षक संगठनों को विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है कि शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी।

अनुपस्थित शिक्षकों को जारी होगा नोटिस

पहले दिन की परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले 58 शिक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। उपयुक्त कारण होने पर (कोरोना संक्रमण इत्यादि) अनुपस्थित शिक्षकों की पुनःपरीक्षा ली जाएगी। इसके लिए अलग से परीक्षा तिथि की सूचना दी जाएगी। उपयुक्त जबाव नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

MP बोर्ड: परीक्षाएं इस बाद देरी से होंगी, ऑनलाइन कराने पर भी विचार

कोरोना काल की वजह से मंडल अप्रैल में कराएगा बोर्ड परीक्षाएं

ग्वालियर। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा इस बार दो माह की देरी से होंगी। बोर्ड परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी, जो मई तक चलेगी। कोरोना संक्रमण बढ़ा तो इसे देखते हुए बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है। पहले प्री-बोर्ड में इसे शुरू किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड परीक्षा में हो सकता है। यह निर्णय मंडल की साधारण सभा की बैठक में सोमवार को लिया गया है। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया। सत्र 2020-21 से बोर्ड परीक्षा देने वाले दसवीं व बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए मंडल ने कई बदलाव किए हैं। इस सत्र से सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी, बल्कि दो मुख्य परीक्षा ली जाएगी। श्रेणी सुधार के लिए विद्यार्थी को अगले साल का इंतजार नहीं करना होगा, दोबारा होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है।

श्रेणी सुधार के लिए छात्रों को नही करना होगा अगले साल का इंतजार

सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी

इस बार बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी। अगर एक बार विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया तो तीन माह बाद वह दोबारा परीक्षा दे सकता है। इसके साथ ही अब मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा या किसी फेल विषय के सामने स्टार नहीं लगेगा। मंडल मुख्य परीक्षा मई तक लेगा और जुलाई में दूसरी परीक्षा लेगा। अगर किसी विद्यार्थी के कम अंक आए हैं तो वह सभी विषयों की परीक्षा भी दोबरा दे सकता है या सिर्फ एक या दो विषय में फेल है तो वह दूसरी परीक्षा में उसी विषय में बैठ सकता है। अगर वह सभी विषयों की परीक्षा देना चाहे तो दे सकता है। जिस परीक्षा में अधिक अंक मिलेंगे, उसे मान्य किया जाएगा। उसी साल रिजल्ट में सुधार आ जाएगा।

इनका कहना है

कोरोना महामारी के कारण इस बार बोर्ड परीक्षाएं देर से शुरू करने का फैसला लिया गया। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से परीक्षा शुरू होगी। साथ ही पूरक परीक्षा के बदले दोबारा परीक्षा होगी। मार्कशीट पर भी सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा।

उमेश कुमार सिंह
सचिव, मंडल

ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर सौंपी जाएगी कॉलेज की जिम्मेदारी

480 प्रोफेसर्स को ट्रेंड कर बनाएंगे UG-PG कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग को सीधी भर्ती और पदोन्नति से बने प्रोफेसरों की अंतिम वरिष्ठता सूची करने में पसीना छूट रहा है। इसके चलते प्रदेश के 480 कॉलेजों में अनुभवहीन प्रोफेसर प्रभारी प्राचार्य बने हुए हैं। इससे विभागीय गतिविधियों में काफी परेशानी आ रही है। इसलिए विभाग ने 480 सीनियर प्रोफेसर को ट्रेनिंग देकर प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश टुडे एजुकेशन

प्रदेश के 516 यूजी-पीजी कॉलेज में से सिर्फ 43 नियमित प्राचार्य पदस्थ हैं। इसमें तीन भोपाल के स्टेट लॉ कॉलेज सुधा बैसा, एमएलबी प्राचार्य डॉ. मंजूला शर्मा और भेल कॉलेज में मथुरा प्रसाद शामिल हैं। शेष 473 कॉलेजों में वरिष्ठ प्रोफेसरों को प्राभारी प्राचार्य बनाकर पदस्थ किया गया है, लेकिन उनकी गतिविधियों में विवाद की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसकी शिकायतें विभाग तक पहुंच रही हैं। इसलिए विभाग ने 480 सीनियर प्रोफेसर को प्रशासनिक ट्रेनिंग देकर प्रभारी प्राचार्य बनाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनिंग प्रशासन अकादमी से ऑनलाइन दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें वित्तीय, आचरण नियम सहित अन्य व्यवस्थाओं से ट्रेंड किया जाएगा, ताकि उन्हें कॉलेजों में कार्य करने में कोई परेशानी नहीं आए। प्राचार्य नहीं बनने की दशा ट्रेंड प्रोफेसर में कॉलेज की गतिविधियों का संचालन करेंगे, जिससे आर्थिक के अलावा किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

विवाद से बिगड़ रहा माहौल

478 कॉलेजों में विभाग ने वरिष्ठ प्रोफेसर के अलावा जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया है। इससे कॉलेजों में आए दिन विवाद होते हैं, जिससे कॉलेजों का माहौल बिगड़ रहा है। कई कॉलेजों में वरिष्ठ प्रोफेसर प्रभारी प्रावार्य रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए कई सीनियर प्रोफेसरों ने प्रभारी प्रावार्य का पद छोड़ने विभाग को आवेदन तक दिए हैं। इससे जूनियर को प्रभारी प्रावार्य का प्रभार दिया जा रहा है। इसके बाद भी विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जूनियर प्रोफेसर प्रावार्य होने पर कई आर्थिक के साथ प्रशासनिक अनिमितताएं कर रहे हैं।

नहीं मिलेगा विशेष भत्ता

नियमित पीजी प्रावार्य को तीन हजार और डिग्री प्रावार्य को दो हजार रुपए का विशेष भत्ता दिया जाता है। प्रभारी प्रावार्य को उक्त भते की पात्रता नहीं होती है, लेकिन उन्हें प्रावार्य का पदनाम जरुर मिल जाएगा। इससे विभाग को करोड़ों रुपए की बचत भी होगी।

इस बार दो महीने देर से शुरू होगी माशिमं की बोर्ड परीक्षाएं

भोपाल। कोरोना संकट के कारण इस बार दो महीने की देरी से माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर मई तक चलेगी। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है। पहले प्री-बोर्ड में इसे शुरू किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड परीक्षा में हो सकता है। यह निर्णय मंडल की साधारण सभा की बैठक में लिया गया है। बैठक में मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया, सचिव उमेश कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक बलवंत वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल की समिति का गठन किया जा चुका है। समिति गठित होने के बाद मंडल की सोमवार को साधारण सभा की पहली बैठक हुई। इसमें मंडल की परीक्षा, वित्त संबंधित अन्य बिंदुओं का अनुमोदन कराया गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया। सत्र 2020-21 से बोर्ड परीक्षा देने वाले दसवीं व बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए मंडल ने कई बदलाव किए हैं।

कोचिंग संचालकों के 25% फीस बढ़ाने का प्लान फेल

भोपाल। करीब 9 महीने के बाद कोचिंग संस्थानों के ओपिनिंग होते ही संचालकों ने 25 फीसदी फीस बढ़ाने का प्लान बनाया था। अब उस प्लान पर पानी फिर गया है। जिला प्रशासन ने फीस बढ़ाने की बात सामने आने के बाद रिव्यू कर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की थी। जिला प्रशासन ने एक जनवरी से 50 फीसदी के साथ कोचिंग खोलने की गाइडलाइन अनुमति जारी की थी। इस पर कोचिंग संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय तिवारी का तर्क था कि आधी क्षमता के साथ रेग्युलर कक्षाएं लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे संस्थानों को घाटे से ऊबारा जा सके। जिसे कलेक्टर अविनाश लवानिया ने खारिज कर दिया।

दक्षता परीक्षा • 10200 शिक्षकों को देनी थी परीक्षा, इनमें से 577 रहे गैरहाजिर

भोपाल के 4, प्रदेश के 900 से ज्यादा शिक्षक फेल

अनूप दुबोलिया | भोपाल

शिक्षकों की दक्षता परीक्षा में भोपाल के 4 और प्रदेशभर में 900 से ज्यादा शिक्षक फेल हो गए हैं। 10वीं-12वीं की सालाना परीक्षा में 40 फीसदी से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों की यह परीक्षा ली गई थी। विभाग ने हाई और हायर सेकंडरी व उनके दायरे में आने वाले मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की रविवार और सोमवार को परीक्षा ली थी। प्रदेश के करीब 10200 शिक्षकों को परीक्षा देनी थी। इनमें से 577 शिक्षक कई कारणों से गैर हाजिर रहे। राजधानी के 62 शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होना पड़ा। दूसरे दिन हुई मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा में भोपाल के 3 शिक्षक नहीं पहुंचे। डीईओ ने इन्हें नोटिस थमाए हैं। परीक्षा होने के बाद इनका सेंटर पर ही मूल्यांकन करा लिया गया है। इसके बाद संचालनालय लोक शिक्षण में पूरे प्रदेश के शिक्षकों की जानकारी भेज दी गई है। वहां इनके रिजल्ट का आंकलन किया जा रहा है। विभाग संभवतः एक दो दिन बाद इन शिक्षकों को परिणाम की जानकारी भेज देगा।

दो कहानियां... जो इस परीक्षा पर उठाती हैं सवाल

25 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 15 का इंजीनियरिंग में चयन, फिर भी ली परीक्षा... यह कहानी बाग सेवनिया स्थित मिडिल स्कूल की हेडमास्टर नीलिमा रोजलीन की है। इन्हें दक्षता परीक्षा देनी पड़ी। 10 साल से स्कूल में पदस्थ नीलिमा के स्कूल से 8वीं पास करके 10वीं में पहुंचे 66 में से 25 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में,16 द्वितीय श्रेणी में पास हुए। स्कूल का रिजल्ट 62 फीसदी रहा। इस स्कूल से हायर सेकंडरी में पहुंचे 2 मेधावी विद्यार्थियों को शासन से लैपटॉप मिला। स्कूल में पढ़ चुके 15 विद्यार्थियों का इंजीनियरिंग में चयन हो चुका। नीलिमा कहती हैं पिछले सत्र में मेरे स्कूल से पास होकर 10वीं में पहुंचे 3 विद्यार्थी 90 फीसदी से ज्यादा अंक लाए। इसके बावजूद दक्षता परीक्षा देनी पड़ी। इसी स्कूल की शिक्षक ममता नेमा को भी परीक्षा देनी पड़ी।

पांच महीने पहले रिटायर हो गए, परीक्षा के नाम पर थमाया नोटिस... यह कहानी बड़वानी जिले के शिक्षक अशोक सोलंकी की है। बीते अगस्त में वे रिटायर हो गए थे। स्कूल और परीक्षा से उनका कोई सरोकार नहीं था। जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने के कारण कारण बताओ नोटिस थमा दिया। नोटिस में मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1966 जिक्र किया गया है।

आगे क्या... फेल शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग, मार्च में फिर होगी परीक्षा

दक्षता परीक्षा में 48 फीसदी से कम अंक लाने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद मार्च अंत में इन्हें दक्षता सिद्ध करने के दोबारा परीक्षा देनी होगी। गौरतलब है कि विभाग ने कम रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों की पिछले साल भी दक्षता परीक्षा ली थी। फेल हुए 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई थी। शिक्षकों के संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध कर इन्हें बहाल करने की मांग की थी।

पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जेयू में हंगामा

ग्वालियर| यूजी कोर्सों में सही मूल्यांकन न किए जाने तथा इसके बाद छात्रों की शिकायत भी न सुने जाने का आरोप लगाकर मंगलवार की दोपहर छात्र जीवाजी यूनिवर्सिटी पहुंच गए। छात्र पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद रजिस्ट्रार प्रो. आनंद मिश्रा ने छात्रों को उनकी समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि बीएससी तृतीय वर्ष में भौतिक शास्त्र में मूल्यांकन सही न किए जाने का आरोप लगाकर छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक के ऑफिस में धरना दे दिया था। मंगलवार को भी कुछ छात्र रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर पहुंच गए थे।

सागर मेडिकल कॉलेज में बनेगी वीआरडीएल

भोपाल, भोपाल, (प्रसं)। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब (वीआरडीएल) की स्थापना के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने एक करोड़ 81 लाख 63 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इससे इस क्षेत्र के जिले सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं निवाड़ी क्षेत्र में फैलने वाली स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, कोरोना आदि बीमारियों से संबंधित विभिन्न जांच कम समय में चिकित्सा महाविद्यालय में ही की जा सकेंगी।

एक्स्ट्रा राउंड के बाद भी यूजी-पीजी में 4.67 लाख सीटें खाली

कॉलेजों में एडमिशन का आखिरी राउंड खत्म

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

यूजी-पीजी के लिए चलाया गया एक्स्ट्रा छठा राउंड मंगलवार को खत्म हो गया। इसमें मंगलवार को शाम 5 बजे तक 5, 843 स्टूडेंड ने ही एडमिशन लिया है। इस तरह यूजी-पीजी में एडमिशन का आंकड़ा 5.67 लाख तक पहुंच पाया है, अभी भी 4.67 सीटें खाली हैं।

ज्ञात हो कि इस राउंड में नए रजिस्टर्ड 4717 स्टूडेंट्स में से 4061 ने दस्तावेजों के सत्यापन कराए थे। इस राउंड में उन स्टूडेंट्स ने भी रिपोर्टिंग की थी, जो पिछले राउंड में सत्यापन के बाद एडमिशन नहीं ले सके थे।

यूजी-पीजी की स्थिति

सीटें	10,35,334
पांच राउंड तक प्रवेश	5,61,882
छठे राउंड तक प्रवेश	5,67,725
खाली सीटें	4,67,609

यूजी की स्थिति

कुल सीटें	8,56,130
पांच राउंड तक प्रवेश	4,27,915
छठे राउंड में प्रवेश	3775

पीजी की स्थिति

पीजी में सीटें	1,79,204
पांच राउंड तक प्रवेश	1,33,997
छठे राउंड में प्रवेश	2068

पैरा-मेडिकल की कक्षाएं शुरू करने के निर्देश

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाली संस्थाओं के लिए पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम के व्यावहारिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण के मद्देनजर पैरा-मेडिकल शिक्षण कार्य पुन: शुरू करने के निर्देश दिये। पैरा-मेडिकल शिक्षा में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश-सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने को भी कहा। श्री सारंग की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्यप्रदेश-सह-चिकित्सीय परिषद की 23वीं साधारण सभा की बैठक हुई।

मंत्री श्री सारंग के निर्देश के परिपालन में परिषद कार्यालय द्वारा विभिन्न नए स्नातकोत्तर, स्नातक एवं डिप्लोमा पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रशासकीय अनुमोदन किया गया है। इसमें M.P.T. in Geriatrice, M.O.T. in Pediatrics, Diploma in PFT Technician और Bachelor in Respiratory Therapist पाठ्यक्रमों का परिषद स्तर से संचालन किया जायेगा। इसके अलावा एक वर्षीय पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिये निर्देशित किया गया।

प्रदेश में निवासरतों की सुविधा एवं सुलभता को देखते हुए मध्यप्रदेश के मूल निवासी, जो कि पैरा-मेडिकल शिक्षा प्राप्त किये जाने के लिये अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत हैं, ऐसे छात्रों का मध्यप्रदेश पैरा-मेडिकल कौंसिल में पंजीयन करने के लिये प्रक्रिया को और अधिक सरलता प्रदान करने के दृष्टिकोण से मंत्री श्री सारंग ने छात्रों का पंजीयन उनके द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों का प्रथमत: सत्यापन/पुष्टि के बाद करने के निर्देश दिये, जिससे कि पैरा-मेडिकल कर्मियों को प्रदेश में ही रोजगार मिल सके।

मंत्री श्री सारंग द्वारा निर्देश दिया गया है कि परिषद कार्यालय के उपयोगार्थ मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग क्रमांक-3, बागमुगालिया भोपाल का पीएसपी भूखण्ड क्रमांक-2, एमराल्ड पार्क सिटी के पास बागसेवनिया, जिसका क्षेत्रफल 2871.30 वर्ग मीटर भोपाल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषदए मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिंल, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद के एक भव्य भवन का निर्माण करवाया जाये। उक्त निर्माण कार्य करवाने के लिए सभी औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूरी की जाएं।

20-50 का फार्मूला बन रहा तो फिर सेवानिवृत्ति आयु में असमानता क्यों

कर्मचारियों ने कहा जब यह कार्रवाई हो रही है तो फिर सेवानिवृत्ति आयु एक समान जरूरी

सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर प्रदेश के समस्त जिलों में कलेक्टर को लिखा पत्र

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

20 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु का फार्मूला अपनाकर कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में शासकीय सेवकों ने सेवानिवृत्ति आयु की असमानता पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में सामान्य प्रशासन द्वारा इस मामले में कलेक्टरों को फिर से लिखे गए पत्र को लेकर कर्मचारी सामने आए हैं। जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने जीवन के 50 बसंत पूर्ण कर चुके हैं और 20 साल की सेवा कर ली है। ऐसे लोक सेवकों को सरकार संभावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने की तैयारी कर रही है।इस संबंध में एक बार फिर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। विभाग के द्वारा जारी इस पत्र में वही उल्लेख किया गया है कि सभी विभाग प्रमुखों और कलेक्टरों से 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके और 20 वर्ष की सेवा करने वाले लोक सेवकों की अद्यतन जानकारी मांगी गई थी। लेकिन आज दिनांक तक यह जानकारी विभाग को प्राप्त नहीं हो पाई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि 4 दिसंबर तक अद्यतन जानकारी विभाग को प्रदान की जाना थी, लेकिन कई जिलों से अभी भी यह जानकारी प्राप्त है। इस मामले को लेकर प्रदेश के कर्मचारी नेताओं ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं।

सेवानिवृत्ति आयु पर विचार हो

इस संबंध में वरिष्ठ कर्मचारी नेता भानु तिवारी का कहना है कि जब सरकार 20 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी कर रही है। तो फिर सेवानिवृत्ति आयु में असमानता क्यों है। भानु तिवारी का कहना है कि डॉक्टर और प्रोफेसर की रिटायर उम्र 65 साल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उम्र 62 वर्ष है। जबकि अन्य संवर्ग को 62 साल में ही रिटायर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। भानु तिवारी का कहना है कि 20 और 50 के फार्मूले में सरकार जो कार्रवाई करने जा रही है उसमे गुण दोष को आधार बनाना चाहिए। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली खराब है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। निर्दोष कर्मचारियों पर यह फार्मूला नहीं लगाया जाना चाहिए।

पहले भी लिखे जा चुके हैं इस प्रकार के पत्र

प्रदेश में कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रकार का फार्मूला तैयार करने के लिए सरकार द्वारा पहले भी ऐसे पत्र कलेक्टरों को लिखे जा चुके हैं। हाल ही में जो पत्र लिखा गया है इस में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस जानकारी को तलब करने के पीछे सामान्य प्रशासन विभाग का आखिर क्या मकसद है। वैसे बताना होगा कि पिछले कुछ माह पूर्व भी राज्य सरकार ने इसी प्रकार का एक पत्र कलेक्टरों को लिखा था। जिसमें संकेत दिए गए थे कि 50 वर्ष की आयु और 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले लोक सेवकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाएगी। हालांकि कलेक्टरों को जो पत्र जारी किया गया है उसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी कोई उल्लेख नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे पत्र दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं से अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करना है।

इंटरनेट की मार्कशीट पर गलत तरीके से बढ़ाए नंबर

जेयू की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में आने पर मामले का हुआ पर्दाफाश

ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जीवाजी विश्वविद्यालय में इंटरनेट मार्कशीट पर गलत नंबर बढ़ाने का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद उपकुलसचिव गोपनीय ने शिक्षक को हटाने का प्रस्ताव प्रबंधन को भेज दिया है। विद्यार्थी ने सीएम हेल्पलाइन में मार्कशीट नहीं बनने की शिकायत की थी, जिसके आधार पर रिकार्ड की जांच की गई तो पता चला कि करेक्शन सेल के शिक्षक ने गलत तरीके से नंबर बढ़ा दिए थे।

सीएम हेल्पलाइन पर बीए के एक विद्यार्थी ने शिकायत की थी कि जेयू से उसकी मार्कशीट नहीं मिल रही है। इसके निराकरण के लिए विद्यार्थी का रिकार्ड निकाला गया, चार्ट में विद्यार्थी फेल था। छात्र प्रायोगिक परीक्षा के कारण फेल था, लेकिन शिक्षक ने चार्ट में नंबर बढ़ा दिए। इससे उसने बीए द्वितीय व तृतीय वर्ष कर लिया। जेयू ने छात्र हित को देखते हुए विशेष प्रायोगिक परीक्षा करा दी, लेकिन शिक्षक को हटाने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। मार्कशीट में सुधार के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन चाहा गया है। उप कुलसचिव राजीव मिश्रा का कहना है कि शिक्षक को हटाने का प्रस्ताव भेज दिया है।

कापियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, सिर्फ नंबर को जोड़ा जाएगा

- मंगलवार को बीएससी तृतीय वर्ष की कापियों के पुनर्मूल्यांकन को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की। फैसला लिया गया कि जिन विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन का फार्म भरा था, उनके नंबरों का टोटल किया जाएगा। कापियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। गत दिवस एनएसयूआइ के कार्यकर्ताओं ने उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया था। उन्होंने विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन का भरोसा दिया। इस प्रस्ताव को कुलसचिव के समक्ष रखा गया था।

अभ्यर्थी वर्दीधारी पदों के लिए नहीं कर सकेंगे आवेदन

आयु बढ़ने का मामला : एमपीपीएससी के लिए 11 जनवरी से आवेदन, प्रदेश के 15 हजार अभ्यर्थी होंगे प्रभावित

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने 2020 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए 11 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। इसमें आयु की गणना एक जनवरी 2021 से की जा रही है, जबकि पिछले साल का है।

अब ऐसे में अगर एक जनवरी 2021 से आयु की गणना होगी तो वो जनवरी 1981 से पहले की जिनकी जन्मतिथि है, वे राज्य सेवा परीक्षा के किसी भी पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। वहीं जिनका जन्म 2 जनवरी 1988 के पहले हुआ है, वे वन सेवा सर्विसेस में वन क्षेत्रपाल के लिए सहित अन्य वर्दीधारी पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। वहीं पांच-छह साल से पीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी आयु गणना में संशोधन किया जाए। अगर एक जनवरी 2021 से आयु गणना की जाएगी तो इससे प्रवेश से करीब 10 से 15 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीएससी में चयन होना हर किसी का सपना होता है। पीएससी ने वर्दीधारी पदों के लिए जो उम्र की गणना एक जनवरी 2021 से की है, जिससे कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो रहे हैं।

इस बार देर से भर्तियों के लिए आवेदन कराए जा रहे हैं, ऐसे में कई अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। अगर पीएससी विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उसी कैलेंडर वर्ष में आयु की गणना करता है तो कई अभ्यर्थियों को इससे लाभ मिलेगा। सभी पदों के लिए कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम आयु 21 साल तय की है। वहीं सहायक वन संरक्षक पद पर अधिकतम आयु 40 साल है, जबकि वन क्षेत्रपाल के पद पर अधिकतम आयु 33 साल तय की गई है। राज्य के मूल निवासी को अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

(संबंधित खबरें पेज 4 पर भी देखें)

चार साल से पीएससी की तैयारी कर रहा हूं। इस बार एक जनवरी 2021 की आयु की गणना होने से इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। पिछले का पीएससी भर्ती है तो एक जनवरी 2020 होना चाहिए।

– **शाश्वत गौतम**, अभ्यर्थी

मैं छह साल से पीएससी की तैयारी कर रहा हूं। अगर आयु की गणना एक जनवरी 2020 से की जाए तो कई अभ्यर्थी पात्र हो जाएंगे। नहीं तो कई अभ्यार्थी अपात्र हो जाएंगे। इससे बहुत नुकसान होगा।

– **राहुल घघले**, अभ्यर्थी

परीक्षा जिस वर्ष होती है। उसी वर्ष के एक जनवरी से आयु की गणना होती है। 2021 में पिछले साल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो एक जनवरी 2020 से गणना होनी चाहिए। – **गोपेंद्र दुबे**, मैनेजिंग डायरेक्टर, विन आइएएस इंदौर

मैं सात साल से तैयारी कर रही हूं। अगर एक जनवरी से 2020 से गणना नहीं की गई तो मैं इस बार डीएसपी और आबकारी पद के लिए पात्र नहीं रहूंगी।

– **दीक्षा मिश्रा**, अभ्यर्थी

पशु हानि के 15 हजार रुपये का दिलाया मुआवजा

भोपाल (नप्र)। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सीएम हेल्पलाइन के संतुष्टिकारक समाधान के तहत सीएम हेल्पलाइन के 5 प्रकरणों में मंगलवार को सुनवाई की। तहसील बैरसिया के ग्राम खंडारिया निवासी चरण सिंह यादव को 15 हजार रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की गई।

बोर्ड परीक्षा पैटर्न में किया गया बदलाव छात्र हित में नहीं

भोपाल (दुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान सत्र की परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह बदल दिया गया है। यह छात्र हित में नहीं है। वर्तमान सत्र समाप्ति पर है। इस समय यह निर्णय पूरी तरह से गलत है।

ज्ञात हो कि 21 दिसंबर को मंडल अध्यक्ष द्वारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में यह कहा था कि हम इस बार देखते हैं कितने बच्चे पास हो रहे हैं। यह चरितार्थ हुआ चार जनवरी की बैठक में नए पैटर्न पर परीक्षा कराने की घोषणा कर दी गई।

नवमीं से 12वीं के स्कूल खोलने के आदेश के बाद भी अभिभावक डरे हुए हैं कि कहीं बच्चे कोरोना संक्रमित न हो जाएं। मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संख्या न के बराबर उपस्थिति हो रही है। ऐसे में पूरी तरह से परीक्षा का स्वरूप बदल देना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होना है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने मंडल से मांग की है कि यह निर्णय जो परीक्षा के चंद दिन पहले दिए गए हैं, इसे तुरंत वापस लिया जाए जो भी निर्णय लेना हो सत्र प्रारंभ होने से पहले लिया जाए।

ऑनलाइन डिस्टेंस से बीए, बीकॉम और दो वर्षीय एमबीए को इस महीने मिल सकती है मंजूरी

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नैक से ए-ग्रेड मिलने के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पारंपरिक स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन पद्धति से संचालित कर सकता है। तीन माह पहले विवि द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बैठक बुलाई है। अधिकारियों के मुताबिक मंजूरी मिल सकती है। फिर उसके आधार पर बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम और दो वर्षीय एमबीए पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जा सकेगा। यह प्रक्रिया अगले सत्र में शुरू होगी।

विवि के डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ने जुलाई में तीन वर्षीय एमबीए को दो साल का करने का प्रस्ताव भेजा था। मगर यूजीसी ने नई शिक्षा नीति आने के चलते प्रस्ताव लौटा दिया था। बाद में विभाग ने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमए, एमकॉम पाठ्यक्रम को ऑनलाइन व डिस्टेंस में शुरू करने की इच्छा जताई। अक्टूबर में नए सिरे से प्रस्ताव भेजे गए। डायरेक्टर डॉ. प्रतोष बसंल का कहना है कि यूजीसी ने जनवरी तीसरे सप्ताह में बैठक बुलाई है। विभाग को ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना होगा। उसके बाद यूजीसी प्रस्ताव पर सहमति दे सकती है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम को संचालित करने से पहले विभाग को वीडियो-ऑनलाइन कंटेंट बनाना होगा। यह काम फरवरी से शुरू करने के संकेत मिले हैं। विभाग ने यूजी व पीजी कोर्स के लिए फीस निर्धारित कर दी है। बीए, बीकॉम और बीएससी की सालना फीस नौ हजार, एमए व एमकॉम में 12 हजार और एमबीए में 32 हजार शेड्यूल रखा है। अधिकारियों के मुताबिक सेमेस्टर सिस्टम से कोर्स संचालित किए जाएंगे।

पीएचडी के लिए आरडीसी की बैठक नहीं होने पर हंगामा

इंदौर। पीएचडी में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों की अब तक रिसर्च डिपार्टमेंट कमेटी (आरडीसी) की बैठक नहीं हुई है। इसे लेकर मंगलवार को कुलपति डॉ. रेणु जैन के सामने विद्यार्थियों ने नाराजगी जताई। इसके तुरंत बाद वाणिज्य विषय की आरडीसी की बैठक की तारीख तय कर दी। अधिकारियों के अनुसार वाणिज्य में सर्वाधिक छात्र-छात्राएं हैं। इसलिए दो दिन तक कमेटी साक्षात्कार लेगी। पीएचडी वाले कई विद्यार्थी छात्रनेता विवेक सोनी-अभिनव हार्डिया के नेतृत्व में कुलपति से मिले। उनका कहना है कि डाक्टोरल एंट्रेस टेस्ट (डीटीई) के जरिए विद्यार्थियों का चयन हुआ। जनवरी 2018 में कोर्स वर्क पूरा हुआ। इसके बाद आरडीसी होनी थी। इसके बादही विद्यार्थी शोध कार्य शुरू कर सकते थे, लेकिन दिसंबर 2020 तक कई विषयों की आरडीसी की बैठक नहीं हुई है।

एलएलएम की ऑनलाइन परीक्षा पर असमंजस

इंदौर। विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन परीक्षा होनी है। इसके लिए बुधवार को विवि ने मॉक टेस्ट रखा है, लेकिन ठीक एक दिन पहले एलएलएम के विद्यार्थियों ने परीक्षा का विरोध कर दिया। उनका कहना था एलएलएम कोर्स की चार माह पहले ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराई है। अब ऑनलाइन ली जा रही है। आपत्ति के बाद विवि ने डीन से मार्गदर्शन मांगा है। अधिकारियों ने अगले सात दिनों में स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया है। मंगलवार को विभिन्न कॉलेजों से एलएलएम करने वाले विद्यार्थियों ने परीक्षा को लेकर विरोध जताया। छात्रनेता विवेक सोनी और अभिनव हार्डिया के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी के सामने समस्या रखी। डॉ. तिवारी का कहना है कि डीन की राय मिलने के बाद फैसला लेंगे।

महाविद्यालय में प्रायोगिक कक्षाएं प्रारंभ

भास्कर न्यूज | सतना. शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहित कन्या महाविद्यालय और सभी शासकीय कॉलेजों में प्रायोगिक कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं, लेकिन प्रायोगिक कक्षाओं में शामिल होने के लिए बहुत कम संख्या में छात्र कॉलेजों में पहुंच रहे हैं। कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. नीलम रिछारिया ने बताया कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार छात्राओं को गुरप में बांटकर प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन में एक ही कक्षा की छात्राओं को बुलाया जा रहा है, जिनसे बॉटनी, जियोलॉजी, कैमेस्ट्री के प्रैक्टिकल एक ही दिन में कराए जाते हैं। इस व्यवस्था से महाविद्यालय में भीड़ बढऩे की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि बीएस-सी विज्ञान समूह एवं एमएस-सी में मिलाकर करीब 4 हजार छात्राएं हैं, जिनके प्रैक्टिकल कराए जाने हैं। इसी प्रकार स्वशासी महाविद्यालय में सिर्फ 5 प्रतिशत ही छात्र प्रायोगिक कक्षाओं में पहुंच रहे हैं, जबकि महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा लगातार छात्रों को प्रायोगिक कक्षाएं प्रारंभ हो जाने की सूचनाएं भेज रहा है।

प्रतिदिन भेजी जाती है रिपोर्ट

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1 जनवरी से प्रायोगिक कक्षाएं प्रारंभ करने का आदेश जारी किया गया था लेकिन जिले के प्रमुख विद्यालयों में अभी तक पर्याप्त छात्र संख्या प्रायोगिक कक्षाओं में नहीं पहुंच रही है। महाविद्यालय प्रबंधन को प्रतिदिन की उपस्थिति उच्च शिक्षा विभाग को भेजनी पड़ती है।

मेडिकल ऑफिसर और सहायक संचालक उद्यानिकी की साक्षात्कार से होगी भर्ती

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

- एमपी पीएससी ने जारी किया 2021 का परीक्षा कैलेंडर, 2019 में जारी हुए विज्ञापन की भी दो परीक्षाएं शामिल

एमपी पीएससी ने 2021 की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की 8 प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं समेत 12 परीक्षाएं होंगी। वहीं मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल व नॉन मेडिकल) और सहायक संचालक उद्यानिकी के पद सीधे साक्षात्कार से भरे जाएंगे। हालांकि इन परीक्षाओं के नियम व शर्तें विज्ञापन जारी होने के बाद ही पता चल सकेगी। जारी कैलेंडर के अनुसार राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020 ऑनलाइन 13 जून को आयोजित होगी। जून में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बाद जुलाई में साक्षात्कार और अगस्त में अंतिम चयन परिणाम जारी किए जाएंगे। इसी तरह सहायक प्रबंधक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परीक्षा जून में होगी। इंटरव्यू अगस्त में और अंतिम चयन परिणाम सितंबर में जारी किए जाएंगे।

MPPSC

राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा का शेड्यूल

कैलेंडर के मुताबिक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019 मार्च में आयोजित होगी। जून-जुलाई में रिजल्ट आने के बाद अगस्त-सितंबर में इंटरव्यू होंगे। अंतिम चयन परिणाम सितंबर में घोषित होंगे। इसी तरह राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019 की मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में आयोजित होगी। रिजल्ट मार्च में आएंगे। अप्रैल में इंटरव्यू होने के बाद इसी माह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं राज्य सेवा परीक्षा-2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल को आयोजित होगी। मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होने की संभावना है।

स्कूल शिक्षा मंत्री से मिले अतिथि शिक्षक

भोपाल। लंबे समय से नियमितीकरण को लेकर संघर्ष कर रहे अतिथि शिक्षक मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परिहार से मिलने पहुंचे और अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग रखी। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने बताया कि स्कूल शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए विमर्श पोर्टल अपडेट करने एवं ज्वाइनिंग की तारीख 20 जनवरी करने का आग्रह किया है। परिहार ने कहा कि प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के हजारों अतिथि शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से मजबूरी में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

जेल प्रेहरी भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (एमपीपीईबी) ने एमपी जेल प्रेहरी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। जिसे उम्मीदवार पीईबी की अधिकृत वेबसाइट पर देख सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर, जन्म तिथि और परीक्षा की तारीख एंटर करनी होगी। इसमें यदि किसी को आपत्ति है तो वह निर्धारित सीमा में दर्ज करा सकते हैं। एक बार संशोधित उत्तर देने के बाद, पीईबी जेल प्रेहरी परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। इस लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी। इसके बाद, चिकित्सा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाओं के चरणों को पूरा किया जाएगा।

अतिरिक्त छठवें राउंड का समापन

यूजी-पीजी में 5843 एडमिशन, 4 लाख 67 हजार खाली रह गई सीटें

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी-पीजी के लिए चलाए गए अतिरिक्त छठवें राउंड का मंगलवार को समापन हो गया। इस राउंड में 5843 स्टूडेंड ने ही यूजी-पीजी में एडमिशन लिया है। इस तरह सभी राउंड के बाद यूजी-पीजी में एडमिशन का आंकड़ा 5 लाख 67 हजार तक ही पहुंच पाया है, अभी भी 4 लाख 67 हजार सीटें खाली हैं। ज्ञात हो कि इस राउंड में नए रजिस्टर्ड 4717 स्टूडेंट्स में से 4061 ने दस्तावेजों के सत्यापन कराए थे। इसके अलावा इस राउंड में उन स्टूडेंट्स ने भी रिपोर्टिंग की थी, जो पिछले राउंड में पंजीयन व सत्यापन कराने के बाद एडमिशन नहीं लिया था।

बीएड में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के पाठ्यक्रमों बीएड, एमएड, बीएडएमएड, बीएबीएड, बीएससीबीएड और बीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का चौथा चरण 31 दिसंबर से 12 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। चार जनवरी तक फॉर्म भरे गए। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक दस्तावेजों का सत्यापन किया। पांच जनवरी की शाम 6 बजे मेरिट सूची जारी की गई।

"क्लास रूम" का प्रसारण कार्यक्रम जारी

सीधी(नवस्वदेश)। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि जनवरी 2021 माह में 1 से 3 जनवरी एवं 26 जनवरी को प्रसारण नहीं किया जायेगा । कक्षा 9वीं एवं 11वीं हेतु सोमवार से शुक्रवार प्रसारण किया जायेगा तथा 6वीं से 8वीं के लिये सोमवार से शनिवार तक प्रसारण किया जायेगा। कक्षा 6वीं से 8वीं के लिये प्रत्येक कक्षा के लिये प्रत्येक कक्षा के लिये सप्ताह में छः-छः एपिसोड के मान से कुल 72 एपिसोड तथा कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिये पांच-पांच एपिसोड के मान से कुल 40 एपिसोड प्रसारित होगें। कुल मिलाकर जनवरी माह में 112 एपिसोड का प्रसारण किया जायेगा। उन्होने बताया कि सभी कक्षाओं के लिए स्पोकन इंग्लिस कक्षा का प्रसारण प्रातः 9:30 बजे से 10 बजे तक किया जायेगा। कक्षा 11वीं का प्रसारण प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक, 8वीं का प्रसारण 11 बजे से 11:30 बजे तक, 7वीं का प्रसारण 11:30 बजे से 12 बजे तक, 6वीं का प्रसारण दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक एवं 9वीं का प्रसारण शाम 3 बजे से 4 बजे तक किया जायेगा।

आर्थोपैडिक सर्जन, शिक्षक सहित 30 संक्रमण की चपेट में

ग्वालियर, न.सं.

कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार को जहां 30 मरीजों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं हमीरपुर निवासी एक महिला की संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। हमीरपुर निवासी 46 वर्षीय ज्ञानवती देवी को कोरोना होने के चलते पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई। इसी तरह गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय की वायरोलॉजिकल लैब की जांच में सात, जिला अस्पताल मुरार की रैपिड एंटीजन टेस्ट की जांच में आठ तथा निजी लैब की जांच में 15 कोरोना संक्रमितों को मिला कर कुल 30 मरीज सामने आए हैं।

फाइल फोटो

संक्रमितों सिटी सेन्टर निवासी 35 वर्षीय चिकित्सक को संक्रमण की पुष्टि हुई है। चिकित्सक अशोक नगर के जिला अस्पताल में आर्थोपैडिक सर्जन हैं। इसी तरह विनय नगर निवासी 40 वर्षीय संक्रमित बिलौआ के एक शासकीय विद्यालय में शिक्षक हैं। शिक्षक ने बताया कि उसे कोई लक्षण नहीं है। विद्यालय में गत दिवस शिविर लगा था, जिसमें उसने अपना नमूना दिया था। इसके अलावा पुलिस की विशेष शाखा में पदस्थ 32 वर्षीय आरक्षक को पिछले एक सप्ताह से बुखार आ रहा था, इसलिए जांच कराई तो संक्रमण की पुष्टि हुई। जबकि माधव नगर निवासी 23 वर्षीय युवक को संक्रमण निकला है। युवक का कहना है कि उसके खांसी के साथ ही कफ आ रहा था। साथ ही भोपाल से लौटे ग्वालियर निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति भी संक्रमण की चपेट में हैं। उधर थाटीपुर निवासी 34 वर्षीय सी.ए. एवं लश्कर निवासी 58 वर्षीय व्यक्ति को भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन मरीजों को मिला कर जिले में संक्रमितों की संख्या 17,386 पहुंच गई है। जबकि 292 लोगों की संक्रमण के चलते मौत भी हो चुकी है।

यूके से लौटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर व उसके पिता का फिर पहुंचा नमूना

ग्वालियर, न.सं.। यूके से लौटे विनय नगर निवासी 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर व उसके पिता का दोबारा नमूना भेजा गया है। जबकि दिल्ली से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 27 दिसंबर को कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद युवक के घर के सदस्यों की जांच कराई तो उसके पिता को भी संक्रमण निकला था। इस पर दोनों को जिला अस्पताल में ही भर्ती रखा गया है। उधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का खुन का नमूना जांच के लिए 28 दिसंबर को नेशनल कम्युनिकल डिसीज सेंटर (एनसीडीसी) दिल्ली भेजा गया था। लेकिन अभी तक इंजीनियर की रिपोर्ट नहीं आई है। जबकि इंजीनियर व उसके पिता में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। इसी के चलते सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा के निर्देश पर मंगलवार को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके पिता तथा उसके संपर्क में आने वाला हौजरी के सेल्समैन का दूसरा नमूना जांच के लिए वायरोलॉजिकल लैब भेजा गया है। डॉ. शर्मा का कहना है कि भोपाल वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा जाएगा कि अगर दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आती है तथा दिल्ली से रिपोर्ट आने में और विलंब होता है तो उस दिशा में मरीज की छुट्टी कर दी जाए या नहीं।

जिले के 216 सरकारी स्कूलों का होगा आधुनिकीकरण

ग्वालियर, न.सं.

जिले के 216 शासकीय विद्यालयों का राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सीएम राइज योजना के तहत आधुनिकीकरण किया जाएगा। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक शिक्षा सुविधाए जुटाई जाएंगी। श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक में जिले में 216 चयनित विद्यालयों के आधुनिकीकरण से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मंगलवार को जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई प्रशासकीय समिति की बैठक में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, रूरबन मिशन, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं आदि विषयों की समीक्षा की गई। प्रशासकीय समिति की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा यादव ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की सतत निगरानी करने पर बल दिया। बैठक में मोहना स्थित सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित करने का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में समिति के उपाध्यक्ष शांतिशरण गौतम तथा समिति के सदस्यगण गिर्राज धाकड़, शत्रुघन सिंह यादव, भगवानलाल आदिवासी व विधायक प्रतिनिधि सुरेन्द्र सिंह गुर्जर सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। संचालन जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. विजय दुबे ने किया।

शासकीय आईटीआई में 15 जनवरी को आयोजित होगा रोजगार मेला

मेले में आयेगी 21 कंपनियां

सतना (नव स्वदेश)। शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये जिला प्रशासन एवं रोजगार कार्यालय के संयोजन में आगामी 15 जनवरी को शासकीय आईटीआई कालेज बिड़ला रोड में जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा। रोजगार मेला प्रातः 10.30 बजे से प्रारंभ होगा। रोजगार मेले में 21 कंपनियों एवं उद्योग केन्द्रों को आमंत्रित किया गया है।

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने बताया कि रोजगार मेले में एल एंड टी स्टील डेवलपमेंट, शिवशक्ति प्रा.लि., प्रतिभा सिंटेक्स प्रा.लि., भारतीय जीवन बीमा निगम, ग्रो फास्ट प्रा.लि., परम स्किल ट्रेनिंग ई.प्रा.लि., बजाज एलियांज इंश्योरेंस, द ई-पाई डॉट कॉम, जिज्ञासा माइक्रोफायनेन्स, तराशना माइक्रोफायनेन्स, एयरटेल पेमेन्ट बैंक, वेलस्पन इण्डिया प्रा.लि., प्रगतिशील बायोटेक, सिगनेट इण्डस्ट्रीज, एण्ड्रायड इण्डस्ट्रीज, क्रोमवेल इंजीनियरिंग लि., पॉथवे कांसलटिंग सर्विसेस, बायोकेयर, श्री इम्प्लेक्स, इण्डो फार्मा एवं अन्य कंपनियों द्वारा 5वीं से स्नातक, डिप्लोमा एवं आईटीआई के समस्त ट्रेडों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार मेले में युवक/युवतियां मूल अंकसूची एवं छायाप्रति, निवास प्रमाण-पत्र, वोटर आईडी कार्ड/आधार कार्ड, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन (यदि हो तो), नवीनतम छः पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ उपस्थित हों। रोजगार मेले में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।

केसी जैन कालेज की मान्यता समाप्त

सतना। जमीनों के फर्जीवाड़े की नींव पर खड़े कामता टोला स्थित केसी जैन कालेज प्रबंधन को नियमों का उल्लंघन व कालेज संचालन में की गई मनमानी महंगीपड़ गई है। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल ने आदेश क्रमांक-2157/415/आउशि/सम्बद्धता जारी करते हुए अशासकीय केसी जैन महाविद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी है।

विवादित भूमि पर संचालित था कालेज

जिला कलेक्टर द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनुसार केसी जैन कालेज का भवन विवादित भूमि पर था जिसका संचालन कूटरचित दस्तावेजों के सहारे किया जा रहा था। कालेज संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका के नियम (अ)(ब)और (स) में से किसी एक पालन अनिवार्य है लेकिन कालेज का संचालन करने वाली जैन बाल विद्या मंदिर समिति कामता टोला द्वारा किसी भी मापदंड को पूरा नहीं किया गया।

जिला कलेक्टर ने लिखा है कि नियम 2.12 का पालन न होने से माहवद्यिालय संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपायुक्त ने कलेक्टर द्वारा प्रेषित जांच बिंदुओं का अध्ययन करते हुए पाया कि लीजडीड, भूमि डायवर्सन, भवन अनुज्ञा आदि दस्तावेज कूटरचित हैं। आयुक्त ने यह भी पाया कि मप्र शासन के 8 अक्टूबर के पत्र क्र. 1808/415/संबद्धता व 29 अक्टूबर को पत्र क्र. 1931/415/संबद्ध के जरिए कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज जमा करने का मौका भी दिया गया लेकिन कालेज प्रबंधन सामने नहीं आया नतीजतन कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर केसी जैन कालेज की मान्यतासमाप्त कर दी गई है।

विवादों के साये में रहा कॉलेज

नियम विरुद्ध कॉलेज संचालन करने वाला केसी जैन कॉलेज प्रबंधन अकसर विवादों में ही रहा है। पहले कालेज प्रबंधन कर्मचारियों को वेतन न देने के मामले में चर्चा में आया फिर छात्र-छात्राओं को टीसी देने में आनाकानी करने के मामले में सुर्खियों में रहा। प्रबंधन के इस रवैये से क्षुब्ध प्रियांशु सिंह, सुधा आर्या, शिवम चौधरी, पुष्पा विश्वकर्मा, प्राची दाहिया, संत कुमार चौधरी, कृष्णा चौधरी आदि छात्र-छात्राओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर टीसी मुहैया कराने की मांग भी की थी।

नियमितीकरण की आस में अतिथि विद्वान

फाइल फोटो

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

नियमितीकरण की मांग को लेकर कमलनाथ सरकार में लगभग छह माह से अधिक समय तक धरना-प्रदर्शन के माध्यम से आक्रोश व्यक्त कर चुके अतिथि विद्वान अब शिवराज सरकार से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं। अतिथि विद्वानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि वे उनके परिवार के भरण-पोषण एवं बच्चों के चौपट होते भविष्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और शीघ्र-अतिशीघ्र सभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करें।

अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत भदौरिया ने कहा है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय उनके धरने में पहुंचे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, सीताशरण शर्मा एवं अन्य विधायक व नेताओं ने कमलनाथ सरकार को कोसते हुए तथा उनकी सरकार बनने पर अविलंब नियमितीकरण का आश्वासन दिया था।

अब मप्र उच्च शिक्षा विभाग में कई वर्षों से सहायक प्राध्यापक के पदों के विरुद्ध अध्यापन कार्य करते रहे अतिथि विद्वान वर्तमान सरकार से अपने नियमितीकरण की बाट जोह रहे हैं। श्री भदौरिया ने बताया कि 450 से ज्यादा अतिथि विद्वान 15 महीने से फालेन आउट हैं। कैसे वो अपने परिवार का भरण पोशण करते होंगे। यह चिंतनीय विषय है, मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वे हमारे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण कर हमारा भविश्य सुरक्षित करें।

परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने उठाए सवाल

स्कूल संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं, बच्चे कैसे हो पाएंगे उत्तीर्ण

भोपाल(आरएनएन)। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा प्रणाली में किए गए बदलाव को लेकर प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि ऑनलाइन पढ़ाई से पूरा अध्यापन करवाया जा रहा है जो संभव नहीं है। क्योंकि प्रदेश में प्रत्येक बच्चे के पास ऑनलाइन अध्यापन के संसाधन नहीं है।

संचालकों के मुताबिक 4 जनवरी 2021 को माध्यमिक शिक्षा मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया की वर्तमान सत्र की परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह बदल दिया गया, जोकि छात्र हित में नहीं है। कोई भी निर्णय कोई भी नियम अथवा बदलाव सत्र के प्रारंभ में होने से पूर्व होना चाहिए। वर्तमान सत्र समाप्ति पर है इस समय यह निर्णय पूरी तरह से गलत है ज्ञात हो कि 21 दिसंबर को अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में यह कहा गया था कि हम इस बार देखते हैं कितने बच्चे पास हो रहे हैं' यह चरितार्थ हुआ 4 जनवरी की बैठक में जो पूरी से गलत है। बच्चे इस बार कोरोना के कारण ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखे हैं ना कि हर वर्ष की तरह पढ़ाई हो रही है। स्कूल 9वीं से 12वीं खोलने के आदेश के बाद भी अभिभावक डरा हुआ है। कारण है कि कहीं बच्चे को कोरोना ना हो जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संख्या ना के बराबर उपस्थित हो रही है। ऐसे में पूरी तरह से परीक्षा का स्वरूप बदल देना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होना है।

प्रदेश में निर्धन बच्चे कैसे करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि प्रदेश में लाखों बच्चे निर्धन है। इनके पास ऑनलाइन पढ़ाई करने की कोई पुख्ता संसाधन नहीं है। वर्तमान सत्र में कोई भी परिवर्तन करना बच्चों के लिए खाई खोदने के बराबर है। आरोप है कि वातानुकूलित कमरे में बैठे अधिकारी इस बात को सोचे सोचे बिना मध्य प्रदेश अभी तक ऐसा प्रदेश नहीं बना है जहां एक एक व्यक्ति के पास ऐसे फोन ऐसी व्यवस्था हो जो राजधानी के एसी में बैठे अधिकारियों के पास है। कोई भी निर्णय सत्र प्रारंभ होने से पूर्व लेना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल से मांग करता है कि यह निर्णय जो परीक्षा के चंद दिन पहले दिए गए हैं इसे तुरंत वापस लिया जाए जो भी निर्णय लेना हो सत्र प्रारंभ होने से पूर्व लिया जाए हम उसका स्वागत करेंगे ।

प्राचार्य और बीईओ की लगी क्लास रिजल्ट कम आने पर हुए नाराज

भोपाल से रीवा पहुंचे शिक्षा विभाग के ओआईसी

सभी बीईओ और प्राचार्यों से 16 बिंदुओं पर मांगी गई कार्य योजना, कार्ययोजना तैयार न करने वालों पर जेडी ने जताई नाराजगी

जागरण, रीवा। स्कूलों में 40 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले प्राचार्यों से रूबरू होने भोपाल से ओआईसी पहुंचे। मंगलवार को डाइट में प्राचार्य और बीईओ की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में सभी को परीक्षा परिणाम बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कमजोर रिजल्ट पर नाराजगी भी जताई।

मिली जानकारी के अनुसर रीवा जिले के लिए नियुक्त ओआईसी सुरेश प्रसाद त्रिपाठी उप संचालक की अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट रीवा के सभागार में जिले के प्राचार्यों की आवश्यक शैक्षणिक समीक्षा बैठक दो पालियों में आयोजित की गई। इसमें प्रथम पाली में विकास खंड रीवा, रायपुर कर्चुलियान, सिरमौर एवं गंगेव के विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा सभी प्राचार्य अपने अपने विकासखंड एवं विद्यालय की कार्य योजना के साथ उपस्थित हुए। पहली पाली की बैठक सुबह 10 बजे से 1.30 बजे तक चली। इसी तरह त्योंथर, नईगढ़ी, मऊगंज की बैठक दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित की गई। बैठक में डीईओ ने हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्यों को परीक्षा परिणाम में सुधार के निर्देश दिए।

साथ ही यह भी निर्देश दिए कि संकुल अंतर्गत कैचमेंट की माध्यमिक शालाओं में पदस्थ योग्यताधारी विषय शिक्षकों से भी आवश्यकतानुसार कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में अध्यापक कार्य कराया जाए। छात्रवृत्ति वितरण शतप्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए फेल खातों की जानकारी एवं उनके अपडेशन का कार्य भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सीएम राइज योजना के अंतर्गत चयनित शालाओं के सत्यापन की कार्यवाही जिम्मेदार अधिकारियों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल माह में सम्पन्न होंगी। इस के अनुसार सभी प्राचार्य समय विभाग चक्र तैयार कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनोयोग से प्रयास करें। प्राचार्यों ने उपर्युक्त निर्देशों का पालन समय सीमा में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।

ओआईसी सुरेश त्रिपाठी ने पूर्व में दिए गए 16 बिंदुओं की समीक्षा की। 40 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले एक-एक प्राचार्य से उनके विद्यालय का परीक्षा परिणाम कम आने का कारण पूछा। वर्तमान सत्र के लिए उनके लक्ष्य की जानकारी एवं उसे प्राप्त करने के आधार पर जानकारी ली गई। जेडी लोक शिक्षण नीरव दीक्षित ने 16 बिंदुओं की कार्य योजना न प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के प्रति अप्रसन्नता जाहिर की।

स्कूलों में शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। सभी विद्यालयों में निदानात्मक कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए । बैठक में प्रमुख रूप से उप संचालक भोपाल सुरेश त्रिपाठी, जेडी, डीईओ के अलावा डाइट प्राचार्य एसएन शर्मा, सहायक संचालक आरती सिंह, सहायक संचालक रमसा डॉ पीएल मिश्रा सहित एपीसी रमसा अजय निगम, ज्ञानपुंज दल, बीईओ व स्कूलों के प्राचार्य मौजूद रहे।

एनएसयूआई ने कहा-कॅरियर मार्गदर्शन योजना में घोटाला हुआ

भोपाल। स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना में करोड़ों घोटाले हुए हैं। यह आरोप मंगलवार को एनएसयूआई के प्रवक्ता सुहृद तिवारी ने लगाए हैं। तिवारी ने उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा कि जिन पर पहले से आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं, उन पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है।

आरोप

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी 325 करोड़ की छात्रवृत्ति

भोपाल, (प्रसं)। मप्रमें पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस वर्ष पिछड़ा वर्ग के दो लाख 49 हजार विद्यार्थियों को 325 करोड़ 23 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की। विभाग ने इस वर्ष पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति में 419 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नात्कोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जा रही है। विभाग ने कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मेघावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति दी जा रही है।

सरकार की बड़ी घोषणा

सरकारी कर्मचारियों के पेंशन नियमों में किया संशोधन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नए साल में एक बड़ी राहत दी है। नए आदेश के तहत पेंशन के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसका देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इस अहम घोषणा में केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए 'विकलांगता मुआवजा' का विस्तार करने का फैसला किया है, अगर वे ड्यूटी की लाइन में अक्षम हो जाते हैं और ऐसी अक्षमता के बावजूद सेवा में बने रहते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि इस कदम से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसे जवानों को विशेष रूप से 'युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर कर्तव्यों के प्रदर्शन में विकलांगता के कारण उनके मामले में रिपोर्ट की जाती है।

एनसीटीई के बीएड सहित आठ कोर्सों के लिए मेरिट लिस्ट जारी

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के आठों पाठ्यक्रमों की मंगलवार को मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। बीएड, एमएड, बीएडएमएड, बीएबीएड, बीएससीबीएड और बीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का चौथा चरण 31 दिसंबर से 12 जनवरी तक होगा। सीटों का आवंटन 9 जनवरी को होगा। 12 जनवरी तक आवंटित छात्रों को कॉलेज में प्रवेश के लिए फीस भुगतान की रसीद और टीसी जमा करनी होगा।

उच्च शिक्षा

विज्ञान यात्रा के 33 फीसदी आवेदन रद्द, फरवरी में होंगे एग्जाम

भोपाल। मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैपकास्ट) द्वारा कराई जाने वाली विज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए अब लगभग 1000 विद्यार्थी परीक्षा दे पाएंगे। विज्ञान यात्रा में शामिल होने 1557 विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें 33 फीसदी विद्यार्थी एप्लीकेशन फार्म सही से जमा नहीं कर पाए। इसलिए मैपकास्ट ने 521 एप्लीकेशन निरस्त कर दिए हैं। मैपकास्ट द्वारा प्रदेश के 1000 स्कूली विद्यार्थियों को इसरो सहित राष्ट्रीय स्तर के पांच विज्ञान संस्थानों और प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कराया जाना है। विज्ञान यात्रा 18 जनवरी से वर्चुअल की जाएगी। इसके लिए मैपकास्ट ने देश के प्रमुख संस्थानों को ईमेल के माध्मय से सूचित कर दिया है।

आरजीपीवी: प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू, थ्यौरी की परीक्षा 20 जनवरी से

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि (आरजीपीवी) द्वारा बीई, बीफार्मा, एमसीए सहित अन्य कोर्स के द्वितीय सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू कर दिए गए हैं, जो 18 जनवरी तक चलेंगे। वहीं 20 जनवरी से थ्यौरी एग्जाम शुरू होंगे।

इस परीक्षा में डेढ़ लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। प्रथम सेमेस्टर के पूर्व व द्वितीय से आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम से होंगी। यूजी-पीजी के प्रथम सेमेस्टर और लेटरल एंट्री से तीसरे सेमेस्टर के रेगुलर विद्यार्थी एग्जाम में शामिल नहीं होंगे। बीई, बीफार्मा, एमसीए सहित सभी कोर्स के सातवें और अंतिम सेमेस्टर की थ्यौरी और प्रायोगिक परीक्षाएं आनलाइन होंगी। विवि के एग्जाम कंट्रोलर प्रो. एके सिंह ने बताया कि कोरोना के चलते सभी कॉलेजों को 18 जनवरी तक प्रैक्टिकल एग्जाम कराने के निर्देश दिए गए हैं।

एक्स्ट्रा राउंड के बाद भी यूजी-पीजी में 4.67 लाख सीटें खाली

कॉलेजों में एडमिशन का आखिरी राउंड खत्म

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

यूजी-पीजी के लिए चलाया गया एक्स्ट्रा छठा राउंड मंगलवार को खत्म हो गया। इसमें मंगलवार को शाम 5 बजे तक 5, 843 स्टूडेंड ने ही एडमिशन लिया है। इस तरह यूजी-पीजी में एडमिशन का आंकड़ा 5.67 लाख तक पहुंच पाया है, अभी भी 4.67 सीटें खाली हैं।

ज्ञात हो कि इस राउंड में नए रजिस्टर्ड 4717 स्टूडेंट्स में से 4061 ने दस्तावेजों के सत्यापन कराए थे। इस राउंड में उन स्टूडेंट्स ने भी रिपोर्टिंग की थी, जो पिछले राउंड में सत्यापन के बाद एडमिशन नहीं ले सके थे।

यूजी-पीजी की स्थिति

सीटें	10,35,334
पांच राउंड तक प्रवेश	5,61,882
छठे राउंड तक प्रवेश	5,67,725
खाली सीटें	4,67,609

यूजी की स्थिति

कुल सीटें	8,56,130
पांच राउंड तक प्रवेश	4,27,915
छठे राउंड में प्रवेश	3775

पीजी की स्थिति

पीजी में सीटें	1,79,204
पांच राउंड तक प्रवेश	1,33,997
छठे राउंड में प्रवेश	2068

जेडी ने किया अगडाल शाउमा. विद्यालय का औचक निरीक्षण

शिक्षक नदारद, डीईओ ऑफिस में अटैच मिला हेडमास्टर

नदारद शिक्षकों का कटेगा एक दिन का वेतन, नोटिस जारी

जागरण, रीवा। मंगलवार को जेडी लोक शिक्षण ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अगड़ाल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में एक भी शिक्षक मौके पर नहीं मिले। हेडमास्टर डीईओ कार्यालय में अटैच मिले। सभी शिक्षकों को नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन काटा जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे जेडी लोक शिक्षण नीरव दीक्षित निरीक्षण करने अगड़ाल स्कूल पहुंच गए। यहां स्कूल का ताला तो खुला था, लेकिन एक भी शिक्षक मौके पर मौजूद नहीं थे। जेडी ने उपस्थिति पंजी देखी तो उसमें भी किसी के हस्ताक्षर नहीं दिखे। प्राचार्य की जानकारी ली गई तो वह डाइट में आयोजित बैठक में शामिल होने गए थे। माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर शैलेन्द्र मिश्रा की जानकारी ली गई तो पता चला कि वह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कई सालों से अटैच में चल रहे हैं। वह स्कूल कभी आते ही नहीं है। इसके अलावा अन्य शिक्षकों की भी जानकारी ली गई तो निरीक्षण के दौरान तक अनुपस्थित रहे। सभी को नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिए गएहैं।

ये मिले अनुपस्थित

जेडी के निरीक्षण में प्रदीप त्रिपाठी उमावि प्रभारी प्राचार्य बैठक में गए थे। इसके अलावा नरेन्द्र मिश्रा, अजय पाण्डेय पीजीबीटी में एमएड करने गए हैं। शैलेन्द्र मिश्रा हेडमास्टर डीईओ कार्यालय में अटैच मिले हैं। सुनील कुमार वर्मा प्राथमिक शिक्षक, ऊषा देवी वर्मा, रचना दीक्षित , राकेश शुक्ला, नीलम अहिरवार, कमलेश सोंधिया, राम स्वरूप मिश्र, सुषमा मिश्रा, रेनू मिश्रा, नत्थू प्रसाद अनुपस्थित पाए गए। सभी को नोटिस जारी किया गया है।

छात्रों के विरोध और कलेक्टर के दखल के चलते नहीं बढ़ पाई कोचिंग फीस

भोपाल। कोरोना संकट के बीच नौ माह की तालाबंदी के बाद 1 जनवरी से प्रशासन ने कोचिंग संचालकों को 50 फीसदी क्षमता के साथ कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन इसके साथ ही कोचिंगों की फीस बढ़ाने का मामला भी सामने आया था। हालांकि छात्रों और अभिभावकों के विरोध और कलेक्टर अविनाश लवानिया के दखल के चलते कोचिंग संचालकों को अपना इरादा छोड़ना पड़ा।

दरअसल कोचिंग संचालकों का तर्क था, कि एक तो उन्हें पहले ही कोचिंग संस्थान बंद रखने से लंबा घाटा हुआ है, दूसरे अब आधी क्षमता के साथ संस्थानों को खोला जा रहा है, ऐसे में जरूरी खर्च निकालने के लिए कम से कम 25 फीसदी फीस बढ़ाई जानी चाहिये। ताकि संस्थानों को घाटे से उबारा जा सके। हालांकि कोचिंग संचालकों के इस प्रस्ताव को कलेक्टर ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही प्रशासन ने रिव्यू कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी गई थी। जिसके बाद कोंचिंग संस्थानों की फीस वृद्वि का मामला खटाई में पड़ गया। गौरतलब है कि, फिलहाल आधी क्षमता के साथ शहर में कोचिंग संस्थाओं का संचालन शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल फीस में बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकेगी। छात्र और उनके अभिभावकों ने भी कोरोनाकाल में फीस बढ़ाने का विरोध किया था।

एनएसयूआई ने लगाया कैरियर मार्गदर्शन योजना में करोड़ों के घोटाले का आरोप

भोपाल। एनएसयूआई की प्रदेश ईकाई ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विवेकानंद कॅरियर मार्ग दर्शन योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। संगठन के प्रवक्ता सुहृद तिवारी ने उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त और निदेशक पर मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाते हुए इन दोनों अधिकारियों को इस घोटालेबाजी का मास्टरमाइंड बताया। तिवारी ने निदेशक पर निशाना साधते हुए कहा कि, इन पर पहले से आर्थिक अनिमितताओं के आरोप लग चुके हैं, उसके बावजूद सरकार इन पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है, तिवारी ने सवाल उठाया कि आखिर अधिकारियों ने बैंक खातों में अपने नंबर क्यों डलवाए।तिवारी ने कहा कि, इन दोनों अधिकारियों आयुक्त उच्च शिक्षा और निदेशक ने उच्च शिक्षा मंत्री को भी गुमराह किया जो अपराध है, ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। एनएसयूआई ने इस मामले को लेकर राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है, संगठन नेताओं का कहना है कि, अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट तक जायेगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोपाल जिलाध्यक्ष आशुतोष चौकसे,मेडिकल विंग समन्वयक रवि परमार,हुजूर विधानसभा अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा,आई टी सेल प्रदेश संयोजक अक्षय परमार,भव्य सक्सेना आदि मौजूद रहे।

एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 10 जनवरी को

जेईई, नीट स्टूडेंट्स को 90 फीसदी तक स्कॉलरशिप का अवसर

कोटा। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित की जाने वाली एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ए-सेट परीक्षा 10 व 17 जनवरी 2021 को होगी। इस परीक्षा में शामिल होकर स्टूडेंट्स फीस में 90 प्रतिशत तक की स्कॉरलशिप प्राप्त कर सकते हैं। एलन द्वारा सत्र 2021-2022 के कोर्स में प्रवेश लेने के लिए यह टेस्ट होगा। वहीं सत्र 2020-2021 के एडमिशन डायरेक्ट बेसिस पर भी जारी हैं।

एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए होने वाले ए-सेट एग्जाम में कक्षा 5वीं से 11वीं के स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं। ए-सेट के माध्यम से हर स्ट्रीम का स्टूडेंट स्वयं का असेसमेंट कर सकता है। यह पेपर साइंटिफिक, अकेडमिक व साइक्लोजिकल असेसमेंट के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें बेस सब्जेक्ट व आइक्यू के प्रश्न होते हैं। पेपर के सांइटिफिक असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट को एलन द्वारा स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। एलन द्वारा जल्दी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को दोहरा लाभ दिया जा रहा है। इसके अनुसार जो स्टूडेंट्स जल्दी एडमिशन लेते हैं उन्हें फीस में रियायत के रूप में लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा यदि वे ए-सेट देते हैं और इसमें भी उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है तो ये दोनों लाभ जल्द प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे।

नर्चर बैच की शुरुआत 19 जनवरी से

2021-22 में 11वीं कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों की जेईई व नीट की तैयारी के लिए एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट द्वारा विशेष नर्चर बैच की शुरुआत 19 जनवरी से की जा रही है। ये वो विद्यार्थी है, जो वर्ष 2023 में जेईई व नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। इस वर्ष कोरोना की वजह से बोर्ड परीक्षाएं मई-जून माह तक आयोजित होने की संभावना है। ऐसे में विद्यार्थियों की जेईई व नीट की तैयारी प्रभावित नहीं हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस नर्चर बैच की शुरुआत की जा रही है।

स्कूलों के कायाकल्प की योजना

सरकारी स्कूलों के बच्चे सीखेंगे संस्कृत, अंग्रेजी में बात करना

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

प्रदेश के 53 सरकारी स्कूलों के बच्चे अंग्रेजी और संस्कृत की पढ़ाई के साथ इन भाषाओं में बात करना सीखेंगे। हर जिले से चयनित एक स्कूल संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी नॉर्थवेस्ट एक्रिडिटेशन कमीशन (एनडब्ल्यूएसी) से जुड़ेगा। मप्र राज्य ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने एजुकेशन फार ऑल योजना के तहत सभी जिलों से तीन स्कूलों के नाम मंगाए थे, जिसमें से एक स्कूल का कायाकल्प के लिए चयन किया गया है। शाजापुर जिल से दो स्कूल शामिल किए गए हैं। योजना के तहत इन स्कूलों का तीन साल के अंदर कायाकल्प किया जाना है। यहां के विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप एलकेजी से कक्षा 12वीं तक शिक्षा दी जाएगी। चयनित स्कूलों के स्टॉफ के बाद लगभग 1300 शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। ये शिक्षक इन स्कूलों के 55 हजार विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इन स्कूलों में 60 फीसदी विद्यार्थियों से ही फीस ली जाएगी। 40 फीसदी विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, बीपीएल के विद्यार्थी होंगे, जिन्हें शुल्क से मुक्त रखने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

प्राचार्यों ने लिया 100 प्रतिशत रिजल्ट देने का संकल्प

वाईसी के नेतृत्व में चली शिक्षा विभाग की समीक्षा, रिजल्ट पर रहा फोकस

रीवा(नवस्वदेश)। जेल मार्ग स्थित सरस्वती स्कूल में जिले के प्रचार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें शामिल प्राचार्यों ने कोरोना की गाइड लाइन का पालन करते हुये बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत रिजल्ट देने का संकल्प लिया। वहीं कुछ प्राचार्यों ने 90, कुछ ने 80 तथा अधिकांश प्राचार्यों ने 50 से 60 प्रतिशत परिणाम देने का संकल्प दोहराया। जानकारी अनुसार समीक्षा बैठक लोकशिक्षण संचालनालय के उपसंचालक व जिले के वाईसी सुरेश त्रिपाठी केमार्गदर्शन में सुबह से लेकर शाम तक चली। इस दौरान श्री त्रिपाठी द्वारा बोर्ड में परीक्षा परिणाम अपग्रेड करने के 20 बिन्दओं के ट्रिप्स दिये। जिस पर जोश में आये सभी प्रचार्यों ने गत वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम की अपेक्षा दुगुना करने के आश्वासन दिये। ये अब रिजल्ट बढ़ाने में कितना खरा उतरते हैं, इसका खुलाशा आने वाले बोर्ड परीक्षा परिणाम से होगा। समीक्षा कार्यक्रम में जेडी नीरव दीक्षित, जिलाशिक्षा अधिकारी आरएन पटेल, आतरी सिंह सहायक संचालक, डाइट प्रचार्य श्यामनारायण शर्मा सहित 240 प्राचार्य शामिल रहे।

40 प्रचार्यों को डीईओ ने जारी की शोकाज

मिली जानकारी अनुसार वाईसी की बैइक से किनारा करने वाले 40 प्राचार्यों को डीईओ ने शोकाज जारी करते हुये एक हफ्ते में जबाव मांगा है। अगर दन प्रचार्यों ने कारण बताओं नोटिस का समय पर जबाव नही दिया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।

दो बार होगा छात्रों का टेस्ट्र

बताया गया है कि खाशतौर पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को अब वाईसी के द्वारा बनाये गये नये शेड्यूल के हिसाब से एक माह में दो बार टेस्ट देना होगा। जिसकी पूरी जानकारी स्कूल बार पोर्टल पर वाईसी को देनी होगी। अगर ऐसा करते प्रचार्य नहीं मिले तो उन पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। समीक्षा बैठक में वाईसी ने कहा सभी प्राचार्य शेड्यूल का निर्धारण करते हुये छात्रों को शैक्षिक स्तर पर अपग्रेड करें ताकि वह परीक्षा में अच्छा परफारमेंस दे सकें।

करो 6 वे वेतनमान का एरियर्स भुगतान

संयुक्त संचालक लोकशिक्षण संचानालय नीरव दीक्षित ने भी वाईसी की तर्ज पर जिला डीईओ की बैठक ली, जिसमें जेडीने सभी को निदेर्शित करते हुये कहा कि डंप राशि में से 6वें वेतन के एरियर्स का भुगतान करें ताकि कर्मचरियों के लाभ मिल सकें। ज्ञात हो कि मंगलवार को बैठक में वित्तीय व्यवस्था को लेकर रही , जिसमें रीवा , सतना, सिंगरौली व सीधी डीईओ शामिल रहे। जिनके द्वारा विभाग में डंप राशि को खर्च नहीं किया जा सका, जबकि मार्च में यह राशि लेप्स हो जायेगी। जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुये जेडी ने राशि को विकास कार्यों सहित कर्मचारियों के लंबित भुगतान में खर्च करने निर्देशित किया।

ग्रामीण महिलाओं के बने स्कूल ड्रेस पहनेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे

जिला स्तर पर एक और नवाचार की कवायद

सतना, (नव स्वदेश)। जिले की शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाले 1.87 लाख स्कूली बच्चे स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार ड्रेस में नजर आएंगे। अगर सब कुछ सही रहा और कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो जल्द ही ड्रेस बनाने का काम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। फिलहाल कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की स्कूल नहीं लग पाई थी, लेकिन आगे जब भी स्कूलों का संचालन होगा तब बच्चे नए ड्रेस में नजर आएंगें। इसके लिये एनआरएलएम मिशन से जुड़ी स्व सहयता समूह की 785 महिलाओं को स्कूली ड्रेस बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

फाइल फोटो

मंगवाई जा चुकी हैं मशीने

इतना ही नहीं जिला पंचायत की ओर से डीएमएफ मद से अत्याधुनिक सिलाई मशीनें भी मंगाई गई है। कोरोना लॉकडाउन काल में मास्क बना कर अपने पैरों पर समूह की महिलाओं को खड़ा करने की अभिनव सफल पहल के बाद अब समूह की महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक और प्रयास है। अगर यह सफल रहता है तो लगभग इससे महिलाओं को लाखों रुपये की आमदनी होगी।

मुफ्त दी जाती है ड्रेस

शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढने वाले विद्यार्थियों को दो जोड़ी स्कूल ड्रेस देने का प्रावधान है। इसके लिये अभी तक शासन की ओर से बच्चों के खाते में 600 रुपये स्कूल ड्रेस के लिए डाल दिये जाते थे। इस राशि का कई मामलों उपयोग नहीं होता था तो काफी संख्या में समरूपता नहीं रहती थी।

मुख्य धरा में लाने की कवायद

बताया गया कि स्वसहायता समूह की महिलाओं को अगर यह काम दे दिया जाए तो वे एक झटके में मुख्य धारा में आ जाएंगी। इसके लिये महिलाओं को एनआरएलएम मिशन के तहत आरसेटी से सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया गया। इधर इस दिशा में शासन स्तर से प्रयास किये जा रहे कि ड्रेस बनाने का काम महिलाओं को मिल जाए। संभवत सकारात्मक संकेत मिलने के बाद अब प्रशिक्षित 785 महिलाओं को विशेषज्ञता के लिए ब्लाक मुख्यालयों में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सभी महिलाओं के पास खुद की भी सिलाई मशीन है।

अत्याधुनिक मशीनें

इस काम के लिये डीएमएफ मद से चार सेंटरों के लिये 20.46 लाख रुपये स्वीकृत कराए थे। इस राशि से अम्ब्रेला मॉडल इलेक्ट्रानिक सिलाई मशीनए इलेक्ट्रानिक कॉज बटन मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कटिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इन्टरलॉक मशीन थी।

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा

शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बनेगी नई नीति

भोपाल निप्र

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि शिक्षकों के तबादले के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। इन्दर सिंह परमार ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' क्रियान्वयन की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बनाई जाने वाली नई नीति को लेकर शिक्षक संगठनों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए जाएंगे। यह नीति प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस मौके पर उन्होंने विभाग की 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' क्रियान्वयन की कार्य योजना के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। इन स्कूलों में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने और उसके क्रियान्वयन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग से समन्वय किया जाए। छात्रों के मूल्यांकन, शिक्षकों के प्रदर्शन के आंकलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तृतीय पक्ष मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाए।

उन्होंने कहा कि चयनित स्कूलों में कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को स्थानीय कुशल कारीगर, कलाकार, शिल्पी आदि हुनरमंद व्यक्तियों से स्थानीय कलाएं हाथ करघा, पेंटिंग, शिल्प आदि विद्या सिखाई जाए। इसके साथ ही शिक्षकों के सतत व्यवसायिक विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण की नीति तैयार करें। इसके मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली तैयार करें। शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली अच्छे प्रदर्शन को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता करेगी।

30 अप्रैल से एमपी बोर्ड, सीबीएसई की 4 मई से शुरू हो सकती हैं बोर्ड की परीक्षाएं

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

एमपी बोर्ड द्वारा 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस सत्र में सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी, बल्कि दो मुख्य परीक्षा ली जाएगी। दूसरी बार आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से आवेदन करना होगा। पहली बार की परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक होगी, वहीं दूसरी बार की परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगी। कोरोना के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि दो बार परीक्षाएं आयोजित होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से किया जा सकेगा। इस बार एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए 18 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। इसमें 10वीं के लगभग 10.50 और 12वीं के करीब 7.50 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। वहीं सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं चार मई से 10 जून 2021 तक आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। जिसके परिणाम 15 जुलाई 2021 तक घोषित करने के प्रयास होंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से शुरू होंगी।

निजी स्कूलों की मांग...

बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलाव को वापस लिया जाए

माशिमं द्वारा कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में किए गए बदलाव को लेकर अब निजी स्कूल विरोध में आ गए हैं। मप्र प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मंडल से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यह बदलाव विद्यार्थियों के हित में नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्तमान सत्र की परीक्षा का पैटर्न बदलने का निर्णय छात्र हित में नहीं है।

अजा-अजजा के प्रतियोगियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

सतना| मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की मप्र लोक सेवा आयोग की प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। प्रोत्साहन योजनांनर्गत प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत 20 हजार रूपए की राशि प्रदाय की जाती है। द्वितीय बार उत्तीर्ण होने पर आधी दस हजार की राशि प्रदान की जाती है। प्रारंभिक परीक्षाफल की प्रति, जाति प्रमाण-पत्र मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आय का प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति आईएफएससी कोड सहित नौकरी में रहते हुए आवेदकों को राशि नहीं दी जाएगी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो तथा हायर सेकंडरी या स्नातक उत्तीर्ण की अंकसूची आवश्यक है।

दूरदर्शन पर होगी छठवीं से आठवीं तक की पढ़ाई

भास्कर न्यूज | सतना

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक तरफ जहां 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है, वहीं प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद रखा गया है। ऐसे में छठवीं से आठवीं के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन से जोड़े रखने और उनका कोर्स समय पर पूरा करने के लिए विभाग द्वारा नई कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत अब कक्षा-6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने टाइम टेबल जारी किया है।

सप्ताह में 6 दिन चलेगा कार्यक्रम

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन से पढ़ाई कराने का जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसके तहत सप्ताह में 6 दिन ही पढ़ाई होगी। यह कार्यक्रम 4 जनवरी से दूरदर्शन से प्रसारित किया जा रहा है। बताया गया कि कक्षावार तय किए गए समय के अनुसार कक्षा-8वीं के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 11 से साढ़े 11 बजे तक पठन-पाठन का कार्य कराया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा-7वीं के लिए साढ़े 11 से 12 बजे तक और कक्षा-6वीं के लिए दोपहर 12 बजे से साढ़े 12 बजे तक वीडियो पाठों का प्रसारण मध्यप्रदेश दूरदर्शन पर किया जाएगा।

स्पोकेन इंग्लिश का भी होगा प्रसारण

कक्षा-9वीं से 12वीं तक के लिए दूरदर्शन पर पहले से ही स्पोकेन इंग्लिश सहित अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। जहां सोमवार से शुक्रवार 12वीं के लिए स्पोकेन इंग्लिश के कार्यक्रम साढ़े 9 से 10 बजे तक, कक्षा-11वीं के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम 10 से 11 बजे और कक्षा-9वीं के कार्यक्रम दोपहर 3 से 4 बजे के मध्य प्रसारित किए जाएंगे।

तैयारी **मंडल परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजेगा, विद्यार्थियों को प्रिंट निकालकर दिए जाएंगे**

इस बार ऑनलाइन होगी 10वीं व 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने कोरोना संक्रमण व नकल रोकने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब दसवीं-बारहवीं की प्री-बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए तैयारियां चल रही है। यदि इसमें सफलता मिली तो बोर्ड की मुख्य परीक्षा में कुछ परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकेगी।

इसके साथ ही दसवीं-बारहवीं के प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन पहुंचेंगे। केंद्र पर ही पेपर प्रिंट कर विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। परीक्षा भी दो पालियों में होगी, ताकि संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। दरअसल, इस बार ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से परीक्षा लिए जाने की तैयारी चल रही है। मंडल सचिव ने परीक्षा केंद्रों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। माशिमं की 10वीं-12वीं परीक्षा में हर वर्ष 19 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसके लिए प्रदेश में साढ़े तीन हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं।

मंडल ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने के साथ ऑनलाइन परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। इसे पहले प्री-बोर्ड परीक्षा में शुरू किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड परीक्षा के कुछ केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की तैयारी है।

– **उमेश कुमार सिंह**, सचिव, माशिमं

निजी स्कूलों में अधिक परीक्षा केंद्र बनेंगे

माशिमं द्वारा परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर निर्देश जारी किए है। इसके तहत निजी स्कूलों में अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। निर्देशों में परीक्षा केंद्रों के लिए ऐसे स्कूलों का चयन करने के लिए कहा गया है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, फोटो कॉपी मशीन उपलब्ध हो या किराए पर आसानी से ली जा सके। साथ ही परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था के लिए फर्नीचर, पेयजल, प्रसाधन व सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। निर्देशों में साफ कहा गया है कि ऐसे कोईभी स्कूल परीक्षा के लिए प्रस्तावित न किए जाएं, जहां टैंट या शामियाना में, टाट पट्टी या जमीन पर परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की स्थिति उत्पन्न हो।

अभी ये है व्यवस्था : माशिमं द्वारा दसवीं व बारहवीं के प्रश्न-पत्र जिले की समन्वयक संस्थाओं में पहुंचाए जाते हैं। समन्वय संस्था द्वारा प्रश्न-पत्रों का वितरण परीक्षा केंद्रों को किया जाता है।

अब यह होगा : अब मंडल द्वारा 2020-21 की परीक्षा में परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न-पत्र ऑनलाइन, पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर प्रिंटर प्रश्न-पत्र निकाले जाएंगे।

इस बार ऑनलाइन ली जाएगी दसवीं और बारहवीं की प्री-बोर्ड परीक्षा

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) ने कोरोना संक्रमण व नकल रोकने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब दसवीं-बारहवीं की प्री-बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। यदि इसमें सफलता मिली तो बोर्ड की मुख्य परीक्षा में कुछ परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकेगी। इसके साथ ही दसवीं-बारहवीं के प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन पहुंचेंगे। केंद्र पर ही पेपर प्रिंट कर विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। परीक्षा भी दो पालियों में होगी, ताकि संक्रमण का खतरा कम किया जा सके।

दरअसल, इस बार ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से परीक्षा आयोजित किए जाने की तैयारी चल रही है। मंडल सचिव ने परीक्षा केंद्रों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। गौरतलब है कि माशिम की दसवीं-बारहवीं परीक्षा में हर वर्ष 19 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसके लिए प्रदेश में साढ़े तीन हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। मंडल की दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक और दूसरी परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक होने की संभावना है।

अभी ये है व्यवस्था

मंडल द्वारा दसवीं व बारहवीं के प्रश्न-पत्र जिले की समन्वयक संस्थाओं में पहुंचाए जाते हैं। समन्वयक संस्था द्वारा प्रश्न-पत्रों का वितरण परीक्षा केंद्रों को किया जाता है।

अब यह होगा

मंडल द्वारा 2020-21 की परीक्षा में केंद्रों पर प्रश्न-पत्र ऑनलाइन, पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन से विद्यार्थियों के लिए प्रश्न-पत्र निकालकर वितरित किए जाएंगे।

मंडल ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने के साथ ऑनलाइन परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। इसे पहले प्री-बोर्ड परीक्षा में शुरू किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड परीक्षा के कुछ केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की तैयारी है।

- **उमेश कुमार सिंह,** सचिव, माशिम

एक लाख से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे शिक्षक

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोनाकाल में प्रवासी श्रमिकों के साथ घर लौटे बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। जबलपुर में 666 बच्चे हैं, जो प्रवासी श्रमिकों के साथ लौटे हैं, जबकि प्रदेश में यह संख्या 1.15 लाख है। राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने जबलपुर सहित प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पत्र भेजा। कलेक्टर, जिला परियोजना समन्वयक सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों की मदद से ऐसे बच्चों को खोजकर स्कूल पहुंचाने का काम करें।

छात्र की अंकसूची में छात्रा की फोटो लगाने पर नोटिस

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर।

मप्र हाईकोर्ट ने छात्र की अंकसूची में छात्रा की फोटो लगाने के बाद उसमें सुधार करने से इनकार करने पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, माशिमं और चैतन्य उमावि साईंखेड़ा गाडरवारा के प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अनावेदकों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। साईंखेड़ा गाडरवारा निवासी टीकाराम पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से वर्ष 2010-11 में दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसकी अंकसूची में जन्मतिथि गलत लिख दी गई थी। उसने अंकसूची में सुधार के लिए आवेदन दिया। वर्ष 2019 में माशिमं ने संशोधित अंकसूची भेजी। संशोधित अंकसूची में उसकी जगह किसी छात्रा का फोटो लगा दिया गया। उसने अंकसूची में दोबारा संशोधन के लिए आवेदन लगाया। माशिमं ने यह कहकर संशोधन करने से इनकार कर दिया कि मामला काफी पुराना हो गया है, इसलिए तीन साल के पहले के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने तर्क दिया कि माशिमं की गलती की वजह से याचिकाकर्ता परेशान हो रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी किया है।

प्रदेश के एक लाख से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे स्कूली शिक्षक

प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग का निर्णय

जबलपुर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोनाकाल में प्रवासी श्रमिकों के साथ घर लौटे बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ेगा इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। जबलपुर में ऐसे 666 बच्चे हैं जो प्रवासी श्रमिकों के साथ लौटे हैं, जबकि प्रदेश में यह संख्या 1.15 लाख है।

राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने जबलपुर सहित प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पत्र भेजा है कि प्रवासी श्रमिकों के साथ घर लौटे बच्चे जो स्कूलों से दूर हैं और जिनकी शिक्षा भी छूट गई है, उन्हें शिक्षा को मुख्य से धारा से जोड़ने के लिए अधिकारियों को प्रयास करना होगा। कलेक्टर जिला परियोजना समन्वयक सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों की मदद से ऐसे बच्चों को खोजकर स्कूल पहुंचाने का काम करें।

बच्चों को यहां दिलाएं प्रवेश

शिक्षा विभाग अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनकी पढ़ाई कराई जाए। इसके अलावा महिला बाल एवं विकास विभाग सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं से मदद लेकर ऐसे बच्चों की मदद की जाए जो बेघर हो चुके हैं। बच्चों को चाइल्ड केयर में डालकर उनकी पढ़ाई शुरू कराई जाए।

घर जाकर पढ़ाएं या स्कूल लाएं

आयुक्त ने लिखा है कि जिला परियोजना समन्वयक अपने जिले के समस्त शिक्षकों की मदद से प्रवासी श्रमिकों के साथ आए बच्चों के घर जाकर अध्यापन कराएं या उन्हें स्कूल लाने का प्रयास करें।

'दूरदर्शन' के माध्यम से होगी विद्यालयीन स्तर की पढ़ाई

जबलपुर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश में कक्षा छठी से 11वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई 'दूरदर्शन' के माध्यम से होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षिक कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन केंद्र भोपाल से क्लासरूम कार्यक्रम का अनुबंध किया है। इसके तहत जनवरी से सप्ताह में छह से सात दिन कक्षाओं का नियमित प्रसारण निर्धारित समय पर किया जाएगा।

जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाना है। इसके लिए काम शुरू कर दिया है। बीआरसी (ब्लाक रिसोर्स कार्डिनेटर), जनशिक्षक सहित शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है।

-आरती चतुर्वेदी, जिला परियोजना समन्वयक

20-50 का फार्मूला बन रहा तो फिर सेवानिवृत्ति आयु में असमानता क्यों

कर्मचारियों ने कहा जब यह कार्रवाई हो रही है तो फिर सेवानिवृति आयु एक समान जरूरी

सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर प्रदेश के समस्त जिलों में कलेक्टर को लिखा पत्र

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

20 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु का फार्मूला अपनाकर कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में शासकीय सेवकों ने सेवानिवृत्ति आयु की असमानता पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में सामान्य प्रशासन द्वारा इस मामले में कलेक्टरों को फिर से लिखे गए पत्र को लेकर कर्मचारी सामने आए हैं। जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने जीवन के 50 बसंत पूर्ण कर चुके हैं और 20 साल की सेवा कर ली है। ऐसे लोक सेवकों को सरकार संभावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने की तैयारी कर रही हैइस संबंध में एक बार फिर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। विभाग के द्वारा जारी इस पत्र में वही उल्लेख किया गया है कि सभी विभाग प्रमुखों और कलेक्टरों से 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके और 20 वर्ष की सेवा करने वाले लोक सेवकों की अद्यतन जानकारी मांगी गई थी। लेकिन आज दिनांक तक यह जानकारी विभाग को प्राप्त नहीं हो पाई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि 4 दिसंबर तक अद्यतन जानकारी विभाग को प्रदान की जाना थी, लेकिन कई जिलों से अभी भी यह जानकारी प्राप्त है। इस मामले को लेकर प्रदेश के कर्मचारी नेताओं ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं।

सेवानिवृत्ति आयु पर विचार हो

इस संबंध में वरिष्ठ कर्मचारी नेता भानु तिवारी का कहना है कि जब सरकार 20 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी कर रही है। तो फिर सेवानिवृत्ति आयु में असमानता क्यों है। भानु तिवारी का कहना है कि डॉक्टर और प्रोफेसर की रिटायर उम्र 65 साल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उम्र 62 वर्ष है। जबकि अन्य संवर्ग को 62 साल में ही रिटायर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। भानु तिवारी का कहना है कि 20 और 50 के फार्मूले में सरकार जो कार्रवाई करने जा रही है उसमे गुण दोष को आधार बनाना चाहिए। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली खराब है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। निर्दोष कर्मचारियों पर यह फार्मूला नहीं लगाया जाना चाहिए।

पहले भी लिखे जा चुके हैं इस प्रकार के पत्र

प्रदेश में कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रकार का फार्मूला तैयार करने के लिए सरकार द्वारा पहले भी ऐसे पत्र कलेक्टरों को लिखे जा चुके हैं। हाल ही में जो पत्र लिखा गया है इस में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस जानकारी को तलब करने के पीछे सामान्य प्रशासन विभाग का आखिर क्या मकसद है। वैसे बताना होगा कि पिछले कुछ माह पूर्व भी राज्य सरकार ने इसी प्रकार का एक पत्र कलेक्टरों को लिखा था। जिसमें संकेत दिए गए थे कि 50 वर्ष की आयु और 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले लोक सेवकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाएगी। हालांकि कलेक्टरों को जो पत्र जारी किया गया है उसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी कोई उल्लेख नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे पत्र दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं से अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करना है।

20:50 मसौदे से बड़ी मुश्किल है आवश्यक सेवानिवृत्ति की डगर

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

शिवराज सरकार कोरोना महामारी के दौरान बिगड़ी राज्य की वित्तीय व्यवस्था के बाद कर्मचारियों से जुड़े 20:50 के मसौदे पर सख्त दिख रही है। गोपनीय चरित्रावली (सीआर) का नंबर गणित भी विभाग ने बदला है। सरकार द्वारा बनाई जा रही नई व्यवस्था में ऐसे नौकरशाहों और कर्मचारियों को आवश्यक सेवानिवृत्ति देने का प्रावधान किया जा रहा है, जिनका काम संतोषजनक नहीं है, अकर्मण्य हैं, कार्य करने में अक्षम हैं, संदेहास्पद हैं और अपनी उपयोगिता खो चुके हैं।

बड़ा सवाल , सेवानिवृत्ति देना आसान नहीं

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को आवश्यक सेवानिवृत्ति देना आसान नहीं है, क्योंकि कर्मचारी की हर साल गोपनीय चरित्रावली तैयार होती है। वहीं कर्मचारी को सूचना के अधिकार के तहत गोपनीय चरित्रावली को देखने का अधिकार भी है। लिहाजा कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ की गोपनीय चरित्रावली में नकारात्मक टिप्पणी करने से कतराता है। जब किसी कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली में कोई नकारात्मक टिप्पणी ही नहीं होगी, तो उसे सेवानिवृत्त कैसे किया जा सकेगा, यह बड़ा सवाल है।

लगातार प्रतिकूल टिप्पणी

सूत्रों के अनुसार आवश्यक सेवानिवृत्ति की परिधि में वे कर्मचारी आएंगे, जिनका काम संतोषजनक नहीं है, अकर्मण्य हैं, कार्य करने में अक्षम हैं, संदेहास्पद हैं और अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। इसके लिए जरूरी होगा कि उनकी गोपनीय चरित्रावली में लगातार कई साल प्रतिकूल टिप्पणी हो। एक तरफ सरकार अक्षम कर्मचारियों की सूची बनवा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 40 से ज्यादा नौकरशाहों की कमजोरियों को एक गुमनाम पत्र के जरिए प्रधानमंत्री तक भेजा गया है, जिसमें से कुछ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि शिकायत से मप्र की खुफिया पुलिस अनजान है, बल्कि उसके पास भी शिकायत और अधिकारियों के नामों के साथ उनकी कमजोरियों की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ वे नाम भी हैं, जिनकी चर्चा हनी ट्रैप मामले में भी दबी जुबान से मंत्रालय व पुलिस मुख्यालय के कक्षों में होती रही है।

हनीट्रेप से जुड़े अधिकारियों पर नजर

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री को मप्र के नौकरशाहों के खिलाफ गुमनाम पत्र के रूप में शिकायत भेजी गई है। इसमें 42 अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य कई आरोपों की शिकायत की गई है। इन अधिकारियों में अधिकांश वरिष्ठ हैं। कुछ नाम हनी ट्रैप मामले की जांच में विवेचना के दौरान भी चर्चा में आए थे। सूत्र बताते हैं कि इन अधिकारियों के आसपास सक्रिय रहने वाले अशासकीय व्यक्तियों के नाम भी शिकायत में बताए गए हैं, जिनके माध्यम से सरकारी काम हासिल करने या अन्य काम करवाए जाने की शिकायत की गई है। इन अशासकीय व्यक्तियों में कई बिल्डर और शिक्षण संस्थाओं से जुड़े लोग भी हैं। ऐसे करीब दर्जन भर लोग तो एक से ज्यादा अधिकारियों के करीबी बताए गए हैं। उपहारों का व्यापार करने वाले एक व्यापारी का नाम तो करीब आधा दर्जन अधिकारियों के करीबी के तौर पर बताया गया है, जबकि एक छापे की कार्रवाई में फंस चुके व्यक्ति को तीन अधिकारियों का निकट बताया गया है। सूत्र बताते हैं कि शिकायत में नौकरशाहों की अवैध कमाई को कहां निवेश किया गया, उसका स्थान भी बताया गया है। कुछ अधिकारियों के मध्यप्रदेश के अलावा विदेश और देश में दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा में निवेश होने की बात कही गई है। कई अधिकारियों के अपने करीबी अशासकीय व्यक्तियों के संस्थानों में निवेश के बारे में भी शिकायत में खुलासा किया है। बिल्डरों के प्रोजेक्ट, होटल और अस्पताल में किए गए निवेश का विवरण भी शिकायत में किया गया है।

आज का इतिहास

1885 भारतेन्दु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रवर्तक का निधन हुआ।

1932 कमलेश्वर - हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ।

1959 कपिल देव, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का जन्म हुआ।

1918 भरत व्यास, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार का जन्म हुआ।

1847 त्यागराज - प्रसिद्ध कवि तथा कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ का निधन हुआ।

2002 काठमाण्डू घोषणा-पत्र में आतंकवाद के खात्मे पर जोर, भारत की राजनीतिक सफलता, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बातचीत के बाद दिल्ली घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर।